(b) whether Government propose to formulate a master plan to tap the fish resources in the sea as well as in inland waters?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PARKASH SINGH BADAL): (a) Yes, Sir. Government is fully aware of the fisheries resources in coastal deep sea and brakish water areas. For optimum utilisation, Government proposes to take the following steps *viz.* chartering of fishing vessels from foreign countries, setting up of joint ventures in collaboration with foreign companies, indigenous construction of fishing vessels, import of new and second hand vessels, scope of shipping development being enlarged in order to facilitate acquisition of fishing vessels, granting of subsidies for indigenous construction of fishing vessels, provision of major and minor fishing harbours at several centres along the east and west coast, provision of infrastructure facilities for storage and marketing, up-dating of the exploratory survey programme and training programme for skilled manpower at various levels to shoulder responsibilities both at sea and at shore, UNDP assistance programme for survey of marine resources, programmes and assistance for commercial survey of deep sea resources.

Small scale fisheries are being developed by National Plan Schemes and bilateral assistance programmes.

For encouraging brakish water fish farming, Government proposes to establish 50 ha Pilot Projects in all the maritime States to encourage commercial farming of prawn and brakish water fishes. For the development of intensive fish culture, the Government have established 23 Fish Farmers' Development Agencies so far during the Fifth Five Year Plan. These Central sector programmes are besides the State Programmes of mechanisation of fishing vessels, fish seed production and fish culture and other programmes to tap all fisheries resources partly. the development needs of the East coast have been particularly kept in view while formulating the schemes.

(b) The Government have worked out plans to tap the resources in sea as well as in inland waters. All the resources are to be exploited under the State Plan schemes and the Central and Centrally sponsored schemes taken under a coordinated programme of fishery development.

Seed Farm in Mehrauli Area of Delhi

135. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) names of the owners of the seed farms along with areas shown against each in Mehrauli area in Delhi nearly the one owned by the erstwhile PM, Mrs. Gandhi; and

(b) Grants and assistance given by Seeds Corporation of India and other Government agencies to Mrs. Gandhi and the other neighbouring owners?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PARKASH SINGH BADAL): (a). In the Revenue Record, no record is kept of seed farms and only the crops are recorded in Khasragdawari by the village Patwari as per the Delhi Land Revenue Rules, 1963. However, there is one Government Seed farm at Hauz Rani measuring about 50 acres of land.

(b) No grants and assistance were provided to Mrs. Gandhi and other neighbouring owners by either the National Seeds Corporation or Delhi Administration.

खेल कूद परिषद् का पुनर्गठन

136. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल कूद को बढ़ावा देने की दृष्टि से खेल-कूद परिषद् का पुनर्गठन किए

जाने का प्रस्ताव है ; यदि हां, तो यह पुनर्गठन कब तक हो जाएगा ;

(ख) खेल -कूद को 'राजनीति' के दलदल, वाह्य एवं आन्तरिक से अलग रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) क्या खेल -कूद में भारत का नाम चमकाने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो , तत्सम्बन्धी रुप-रेखा क्या है और यह कब तक लागू हो जाएगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) से (घ) . अन्तर्राष्ट्रीय ओलिंपिक समिति तथा अन्य संस्थाओं द्वारा निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न खेल कार्यक्रमों तथा नीतियों का शीघ्र ही व्यापक पुनरीक्षण किए जाने का प्रस्ताव है । इस पुनरीक्षण में उन उपायों को भी शामिल किया जाएगा, जो विभिन्न खेल संस्थाओं में देश के खेलों के समुचित विकास में आने वाली अड़चनों को दूर करने तथा भारत को अपना नाम चमकाने के लिए आवश्यक होंगे ।

वर्ष 1975 के दौरान विदेशों में भेजे गये सांस्कृतिक शिष्टमंडल

137. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में आपात स्थिति के दौरान विदेशों में कितने सांस्कृतिक शिष्ट-मंडल भेजे गये और उन में राजनीतिज्ञों की संख्या कितनी थी ।

(ख) विदेशों में संगीत और नृत्य के लिये कितनी मंडलियां भेजी गई और धर्म तथा नैतिकता सहित भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों का प्रचार करने के लिए कितने शिष्टमंडल भेजे गये ;

(ग) क्या इन शिष्ट मंडलों में कोई केन्द्रीय अथवा राज्य. मंत्री भी शामिल था ;

(घ) यदि हां, तो उसका नाम क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) से (घ). 1975 में आपात अवधि के दौरान, संस्कृति विभाग के विभिन्न सांस्कृतिक विनिमय/कार्यकलाप कार्यक्रमों के अन्तर्गत चार गैर-अभिनय सांस्कृतिक शिष्टमंडल विदेशों में भेजे गए थे जिन में विद्वान, कवि, लेखक, नृत्य निर्देशक शामिल थे, तथा सात सांस्कृतिक शिष्टमंडल, जिन में संगीतज्ञ, नृतक तथा कठपुतली वाले शामिल थे । इन सांस्कृतिक विनिमयों का मुख्य उद्देश्य, विदेशों के साथ पारस्परिक सद्भावना को बढ़ाने तथा घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने की दृष्टि से विदेशों में भारत की सांस्कृतिक परम्परा को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना है । इन शिष्ट-मंडलों में कोई भी राजनीतिज्ञ अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य मंत्री शामिल नहीं था ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों तथा फ्लेटों के आवंटन के लिए पंजीकरण

138. **श्री के० लकप्पा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० के प्लाटों तथा फ्लैटों के आवंटन के लिए पंजीकरण बहुत समय तक बंद रहा जिस के फलस्वरूप बहुत से ऐसे व्यक्तियों को भारी असुविधा हुई जिन के अपने मकान नहीं और जो उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं ; और

(ख) यदि हां, इन व्यक्तियों की सहायता करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ताकि कम और मध्य आय वर्ग के व्यक्तियों को कुछ राहत मिल सके ?